2 | दैनिक जागरण पटना, 6 अगस्त 2013

मनरेगा के लिए बना है 500 करोड़ रुपये का कारपस फंड

जागरण ब्यूरो, पटना : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के लिए समय पर केंद्र से राशि नहीं मिलने से होने वाली दिक्कतों से निपटने में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 500 करोड़ रुपये का बना कार्पस फंड बहुत काम आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इसके कारण प्रदेश में 2011-12 की तुलना में 2012-13 में 31 प्रतिशत अधिक राशि खर्च हो सकी। उन्होंने सीएजी की इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया जिसमें 9500 करोड़ की राशि से सूबे के वंचित रहने की बात कही गई है।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा की मौजूदगी में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में मिश्रा ने कहा कि 2011-12 में मनरेगा के तहत सूबे में 1583 करोड़ खर्च हुए, जबकि 2012-13 में 2,061 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके। विभाग ने 2012-13 में 3300 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना भेजी। परन्तु पहली किस्त 50 फीसद यानी 1650 करोड़ की जगह मात्र 700 करोड़ की मिली। केंद्र से उस साल कुल 1250 करोड़ मिले। कार्पस फंड से राशि लेकर योजनाओं को समय पर पूरा किया गया। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में 2600 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना के लिए सिर्फ 1,000 करोड़ मिले। अबतक 700 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

सीएजी रिपोर्ट पर मंत्री ने कहा कि जब मनरेगा आवंटन आधारित नहीं, बल्कि मांग आधारित योजना है, तो 9500 करोड़ रुपये की राशि से प्रदेश कैसे वंचित हो गया? विपक्षी दल भी बिना सोचे समझे यह बात उठा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि प्रखंडों में दी गई राशि का कोई अता-पता नहीं है। हालांकि मनरेगा के वेबसाइट पर हर पंचायत में खर्च की गई राशि का ब्योरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएजी रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की खास चर्चा नहीं है। कुछ बहुत छोटी रकम के मामले हैं।